



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 185]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 1978/चैत्र 16, 1900

No. 185]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 1978/CHAITRA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(भारो उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1978

का० आ० 253(अ) —केन्द्रीय सरकार, ग्रेशम एण्ड क्रेवन ऑफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का धर्जन और अन्तर्गण) अधिनियम, 1977 (1977 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 शक्ति नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का शक्ति नाम ग्रेशम एण्ड क्रेवन ऑफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का धर्जन और अन्तर्गण) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएँ —इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) 'अधिनियम' से ग्रेशम एण्ड क्रेवन ऑफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड (उपक्रमों का धर्जन और अन्तर्गण) अधिनियम, 1977 (1977 का 42) अभिप्रेत है।

(ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3 सूचना देने के लिए समय-सीमा —किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार में, या ग्रेषवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड में या किसी सरकारी कम्पनी में निहित हो गई है, प्रत्येक बन्धकदार और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके सम्बन्ध में कोई

भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जो धारा 17 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना आयुक्त को देगा —

परन्तु यदि आयुक्त का यह समझान हो जाए कि बन्धकदार या कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति, पर्याप्त कारणों से, उक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर सूचना देने में निवारित हो गया था तो, आयुक्त तीस दिन की और अवधि के भीतर किन्तु उसके पश्चात् नहीं, सूचना दे सकेगा।

4 सूचना की रीति —(1) नियम 3 के अधीन आयुक्त को दी जाने वाली हर सूचना, लेखबद्ध रूप में, आयुक्त को संबोधित होगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियाँ होगी, अर्थात् —

(क) बन्धकदार/भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारक का नाम, वर्णन और पूरा पता;

(ख) उस उपक्रम का नाम, जिसकी बाबत दावा किया गया है;

(ग) दावे की रकम (भारतीय करेसी में);

(घ) ऐसी लिखित, यदि कोई हो, की विशिष्टियाँ, जिससे बन्धक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित को प्रतिभूत किया गया हो, इसके समर्थन में लिखन की अनुमति प्राप्त प्रति भेजी जानी चाहिए,

(ङ) रकम, यदि कोई पहले ही प्राप्त की गई हो, और उसकी विशिष्टियाँ,

(च) दावे से सुसंगत कोई अन्य विशिष्टियाँ,

(छ) अनुमति, जिसका दावा किया गया हो।

(2) हर सूचना बन्धकदार या भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जानी चाहिए।

(3) सूचना आयुक्त, के कलकत्ता स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय के समय के दौरान फाइल की जानी चाहिए या आयुक्त की रसीदों रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जानी चाहिए।

[फा० सं० 2(1)/78/एच०एम०-III]

नरेश चन्द्र, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 1978

**S.O. 253(E).**—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1977 (42 of 1977), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

Short title and commencement :—(1) These rules may be called Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :— In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Gresham and Craven of India (Private) Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1977 (42 of 1977);

(b) 'section' means a section of the Act.

3. Time-limit for intimation :— Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government or in the Braithwaite and Company Limited or in a Government Company, as the case may be, and every person holding any charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property, shall give intimation of such mortgage, charge, lien or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date, as may be specified by the Central Government under section 17.

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee or the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may receive the intimation within a further period of thirty days and not thereafter.

4. Manner of intimation :— (1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars, namely :—

- (a) Name, description and full address of the mortgagee/charge, lien or other interest holder ;
- (b) name of the undertaking in respect of which the claim is made ;
- (c) amount of claim (in Indian currency) ;
- (d) particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument ;
- (e) amount, if any, already received, with particulars ;
- (f) any other particulars relevant to the claim ;
- (g) relief claimed .

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge, lien or other interest or a person duly authorised by him.

(3) Intimations may be filed in the office of the Commissioner at Calcutta on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post with acknowledgement due.

[F. No. 2(1)/78-HM-III]

Narash Chandra, Jt. Secy.